

प्रश्न सं. [क. 746]  
मध्यप्रदेश शासन, सिंचाई विभाग

क्रमांक: 15/31/84/मध्यम/अ।  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त, 1988

मुख्य अभियन्ता,  
सिंचाई विभाग,  
भोपाल।

विषय:-सिंचाई विभाग में पीस/वर्क वर्क आर्डर पद्धति द्वारा निर्माण कार्यों का कार्य-  
कार्यान्वयन।

पीस वर्क पद्धति के उपयोग को युक्तियुक्त व नियमित करने के लिये तथा विभिन्न स्तर पर वित्तीय सीमाओं को निर्धारित करने का प्रश्न काफी समय से शासन के विचाराधीन रहा है। विचारोपरान्त शासन ने निर्णय लिया है कि सिंचाई विभाग के समस्त अधिकारी निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे जो दिनांक 16 सितम्बर 1988 से प्रभावशील होंगे।

1/ समस्त निर्माण कार्यों के लिये निविदाएं बुलाना आवश्यक है। यदि दो बार निविदाएं बुलाने पर निविदा न प्राप्त होने के कारण अथवा प्राप्त निविदा में उपयुक्त दर न होने के कारण सक्षम अधिकारी द्वारा ठेके निर्धारित करना संभव नहीं होता है इस हालत में सिंचाई विभाग के अधिकारी नीचे कौडका-3 के अनुसार पीस वर्क/वर्क आर्डर, पद्धति से कार्य कराने के लिये सक्षम होंगे।

2/ आपातकालीन स्थिति एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में अधिकृत के मध्यम से कार्यपालन यंत्री द्वारा भेजे गये प्रस्तावों पर मुख्य अभियन्ता अभिलेख में लिखित रूप से कारण दर्शाते हुए पीस वर्क/वर्क आर्डर पद्धति पर बिना निविदा बुलाए कार्य हाथ में लेने के आदेश इस पत्र की कौडका 3 में दर्शायी गयी परिधि में दे सकेंगे। अधीक्षण यंत्री व कार्यपालन यंत्री को इस विशेष परिस्थितियों में पीस वर्क/वर्क आर्डर पर कार्य कराने का स्वयमेव कोई अधिकारी नहीं होगा एवं मुख्य अभियन्ता के लिखित अनुमति उपरान्त ही पीस वर्क पर ऐसे कार्य किये जा सकते हैं।

3/ उपरोक्त कौडका 1 एवं 2 में दर्शायी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक सिंचाई संभाग में वित्तीय वर्ष में पीस वर्क/वर्क आर्डर प्रणाली द्वारा कार्य निम्नानुसार सम्पादित कराये जा सकते हैं।

अधीक्षण यंत्रों, अपने संभाग/डीडीजन में सभी कार्यों पर प्रतिवर्ष रुपये 2 लाख तक

4/- अधीक्षण यंत्रों अपने मण्डल, के अंतर्गत प्रत्येक संभाग/डीडीजन में रुपये 2 लाख तक वीस वर्क/वर्क आर्डर पर कार्य कराने की अपरोक्त स्वीकृत प्रत्येक वर्ष 30 अर्थात् कार्य हेतु ; अन्त तक प्रभावशील होगी । तत्पश्चात् निविदाएं बुलाकर ठेके निर्धारण के प्रयास नियमानुसार पुनः करने होंगे ।

4/- वीस वर्क/वर्क आर्डर पद्धति पर कार्य कराने के दर निर्धारण एवं अन्य संबंधित पर वर्तमान में निर्धारित प्रक्रिया व निर्देश यथावत रहेंगे । सुलभ सन्दर्भ हेतु संक्षेप में उते परिशीलक-1, में दर्शाया गया है ।

5/- वीस वर्क/वर्क आर्डर पद्धति से कार्य निष्पादन पर नियंत्रण रखने के लिये नियम विधे जाते है ।

1/- कीण्डका 2 में उल्लेखित अपरिहार्य स्थितियों को छोड़कर, वीस वर्क/वर्क आर्डर के अंतर्गत माह की पहली से 10 तारीख तक ही वीस वर्क/कार्यदिश जारी किए जा सकेंगे एवं माह के शेष अर्ध में कोई वर्क आर्डर जारी नहीं किये जावेगा ।

2/- कार्यपालन यंत्रों, प्रत्येक माह उनके संभाग में जारी किये गये वीस वर्क/वर्क की संख्या एवं राशि दर्शाते हुए एक प्रपत्र आगामी माह की 15 तारीख तक अधीक्षण यंत्रों को प्रस्तुत करेंगे । अधीक्षण यंत्रों इसी प्रकार उनके द्वारा जारी किये गये वीस वर्क/वर्क आर्डर एवं उनके अधीनस्थ संभागों में जारी किये गये वीस वर्क/वर्क आर्डर की संख्या एवं लागत की जानकारी सम्मिलित कर एक प्रपत्र आगामी माह की 20 तारीख तक मुख्य अभियन्ता, को प्रस्तुत करेंगे । मुख्य अभियन्ता, सुनिश्चित करेंगे कि माह की 25 तारीख तक पिछले माहने में उनके अधीनस्थ अधीक्षण यंत्रों की जानकारी संकलित कर प्रमुख अभियन्ता को प्रस्तुत करेंगे ।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पाल किया जाय ।

हस्ता/-  
जे०आर०मल्होत्रा  
सचिव,  
म०प्र० शासन, सिंघाई विभाग-

पू० क्रमांक- 15/13/84/मध्यम/31,  
प्रतिनिधि:-

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 1988

तमस्त संबंधित कार्यालयों की ओर सूचनाई अग्रेषित ।

कृपया शासन के निर्देशों को अनुसार उचित कार्यवाही करें तथा कड़ाई से पालन करें ।

हस्ता/-  
जे०सी०उत्तमचन्द्रानी संयुक्त सचिव  
म०प्र० शासन, सिंघाई विभाग,

मध्यप्रदेश शासन  
जल संसाधन विभाग  
मंत्रालय  
वल्लभ भवन भोपाल

परिशिष्ट-2

पत्र क्रमांक 4214028/पार्ट-3/मध्यम/31/2011/928 भोपाल, दिनांक 4/11/2011  
प्रति,

प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग,  
भोपाल

विषय- पीस वर्क पर कार्य करने हेतु शासन के आदेशों में संशोधन ।

संदर्भ- (1) आपका प्रस्ताव एकल नस्ती क्रं. 4214028/पार्ट-3/167/प्रअ/2011 दिनांक  
10-10-2011


(2) शासन का पत्र क्रं. 15/31/84/मध्यम/31 दिनांक 02-09-1988

(3) शासन का पत्र क्रं. 15/31/84/मध्यम/31 दिनांक 20-06-1990

---00---

शासन आदेश क्रमांक 15/31/84/म./31 दिनांक 02 सितम्बर 1988 की कडिका  
क्रमांक-3(क) में प्रत्येक संभाग में ₹ 2.00 लाख तक पीसवर्क पर कार्य करने की सीमा निर्धारित  
है, जिसे संशोधित कर मध्यम एवं वृहद परियोजनाओं के लिए ₹ 20.00 लाख किये जाने जाने  
का निर्णय किया गया है ।

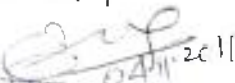
तदनुसार कार्यपालन यंत्री अपने संभाग में अधीक्षण यंत्री की अनुशंसा उपरान्त मुख्य  
अभियन्ता की स्वीकृति से सभी कार्यों पर प्रतिवर्ष ₹ 20.00 लाख तक के कार्य पीस वर्क पर कर  
सकेंगे । शासन आदेश की शेष कडिकायें यथावत रहेंगी ।

  
(अश्विनी कुमार उपमन्यु)  
अवर सचिव

म प्र शासन, जल संसाधन विभाग

पत्र क्रमांक 4214028/पार्ट-3/मध्यम/31/2011/928 भोपाल, दिनांक 4/11/2011  
प्रतिलिपि:-

- (1) अध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल
- (2) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल ।
- (3) महालेखाकार, मध्य प्रदेश ग्वालियर/भोपाल
- (4) सचिव, म प्र शासन, जल संसाधन विभाग
- (5) अपर सचिव, म प्र शासन, पाइकू, जल संसाधन विभाग
- (6) अवर सचिव/वि क अ (यो/ब) म प्र शासन, जल संसाधन विभाग
- (7) समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग को प्रतिलिपि भेजने के लिए ।  
की ओर शासन के निर्देशों के परिपालन में उचित कार्यवाही करें ।

  
(अश्विनी कुमार उपमन्यु)  
अवर सचिव

म प्र शासन, जल संसाधन विभाग